

DAILY CURRENT AFFAIRS

IN HINDI

SPECIAL FOR UPSC & GPSC EXAMINATION

DATE : 20-12-25



The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE

Saturday, 20 Dec, 2025

Edition : International Table of Contents

Page 03 Syllabus : GS 2 : Governance	सीएपीएफ में अग्निवीरों के लिए आरक्षण बढ़ाकर 50 प्रतिशत करेगी सरकार
Page 04 Syllabus : GS 2 : Indian Polity / Prelims	शीतकालीन सत्र 100 प्रतिशत से अधिक उत्पादकता के साथ संपन्न हुआ
Page 05 Syllabus : GS 2 : Social Justice / Prelims	बाल तस्करी एक गहरी परेशान करने वाली हकीकत: सुप्रीम कोर्ट
Page 09 Syllabus : GS 2 : Governance	हैदराबाद नाइटलाइफ़ को जगाने की दिशा में एक कदम और करीब ले जा रहा है
Page 11 Syllabus : GS 3 : Indian Economy	'बहुत कम मुद्रास्फीति चिंता का कारण है'
Page 06 : Editorial Analysis Syllabus : GS 2 : International Relations	एक मजबूत रक्षा औद्योगिक आधार का महत्व

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के ग्रुप सी पदों में पूर्व-अग्निवीरों के लिए आरक्षण को 10% से बढ़ाकर 50% करने का केंद्रीय गृह मंत्रालय का निर्णय अग्निपथ योजना के तहत सेवा के बाद के अवशोषण ढांचे के एक महत्वपूर्ण पुनर्मूल्यांकन का प्रतीक है। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) से शुरुआत करते हुए, यह नीतिगत बदलाव अग्निवीरों के पहले बैच की सेवानिवृत्ति से पहले आता है और नौकरी की सुरक्षा, पुनर्वास और अल्पकालिक सैन्य भर्तियों की सामाजिक स्थिरता से संबंधित लंबे समय से चली आ रही चिंताओं को दूर करने के सरकार के प्रयास को दर्शाता है।

Govt. to increase reservation for Agniveers in CAPFs to 50%

After reserving 50% constable posts in BSF, the Home Ministry moves to enhance the quota in Group C posts for ex-Agniveers in other CAPFs; new policy marks a shift from earlier decision

Vijaita Singh
NEW DELHI

Months before the first batch of Agniveers retires from service, the Union Home Ministry has decided to enhance reservation for ex-Agniveers in the Group C posts of the Central Armed Police Forces (CAPFs) from the existing 10% to 50%, a senior government official told *The Hindu*.

On Friday, the Ministry notified that 50% vacant constable posts in the Border Security Force (BSF) will be reserved for former Agniveers. Though exempted from Physical Standard Test and Physical Efficiency Test, the notification suggests that the ex-Agniveers will have to appear for written examinations like other regular candidates.

The official said that the recruitment rules for Group C posts of all CAPFs will be amended gradually in the coming days. This is a significant shift from Ministry's earlier decision to implement 10% reservation for the temporary recruits



The notification suggests that the ex-Agniveers will have to appear for written examinations like other regular candidates. IMRAN NISSAR

of the armed forces in the CAPFs.

Violent protests in 2022

The recruitment policy announced in 2022 was met with violent protests and was one of the major issues during the 2024 Lok Sabha elections.

Following protests, the Ministry announced that 10% of all vacancies in the CAPFs will be reserved for the armed forces recruits who have completed four years of service under the Agnipath scheme. It also announced five years age relaxation in recruitment

for the first batch and three years age relaxation for subsequent batches. The first batch of Agniveers will be eligible for recruitment in the CAPFs in 2026.

On Friday, the Ministry notified the Border Security Force, General Duty Cadre (Non-Gazetted) Recruitment Rules, (Amendment) Rules, 2025, with new provisions.

The amended Rules say, "By direct recruitment (including fifty per cent vacancies shall be reserved for ex-Agniveers in every recruitment year, ten per cent from ex-Servicemen

and up to three per cent for absorption of annual vacancy amongst Combatised Constable (Tradesmen)."

"In the first phase, the recruitment shall be conducted by the Nodal Force for fifty per cent vacancies earmarked for ex-Agniveers" and "in the second phase, recruitment shall be conducted by the Staff Selection Commission for candidates other than ex-Agniveers for the remaining forty-seven per cent (including ten per cent ex-Servicemen) for the vacancies along with the unfilled vacancies of ex-Agniveers in a specific category in the first stage", it said.

For absorption in the rank of constables from among the Combatised Constable (Tradesmen) of the BSF, the age criteria have been relaxed from existing 30 to 35 years.

The CAPFs comprise the Central Industrial Security Force (CISF), BSF, Central Reserve Police Force (CRPF), Indo Tibetan Border Police (ITBP), Sashastra Seema Bal (SSB) and the Assam Rifles.

पृष्ठभूमि और संदर्भ

- 2022 में शुरू की गई अग्निपथ योजना ने सशस्त्र बलों के लिए चार साल का अल्पकालिक भर्ती मॉडल पेश किया, जिसमें केवल 25% भर्तियों को लंबी सेवा के लिए रखा गया। शेष 75% के नागरिक कार्यबल में फिर से एकीकृत होने की उम्मीद थी।
- हालाँकि, इस योजना को व्यापक विरोध का सामना करना पड़ा, विशेष रूप से सुनिश्चित सेवा-पश्चात रोजगार की अनुपस्थिति पर, जिससे यह 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दा बन गया। जवाब में, सरकार ने शुरुआत में सीएपीएफ में 10% आरक्षण के साथ-साथ आयु में छूट की घोषणा की। कोटा को

50% तक बढ़ाने का वर्तमान निर्णय बड़े पैमाने पर रंगरूटों और समाज के बीच विश्वास बहाल करने के उद्देश्य से एक प्रमुख नीतिगत बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है।

नई नीति की मुख्य विशेषताएं

उन्नत आरक्षण:

- सीएपीएफ में कांस्टेबल (ग्रुप सी) की 50% रिक्तियां पूर्व-अग्निवीरों (बीएसएफ से शुरू) के लिए आरक्षित हैं।
- कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) के माध्यम से भरी गई शेष रिक्तियां, जिसमें भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10% शामिल हैं।

मेरिट-आधारित स्क्रीनिंग:

- पूर्व-अग्निवीरों को शारीरिक मानक और शारीरिक दक्षता परीक्षणों से छूट दी गई है, लेकिन प्रतिस्पर्धात्मक समानता सुनिश्चित करते हुए उन्हें लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

चरणबद्ध भर्ती प्रक्रिया:

- पहला चरण: पूर्व-अग्निवीरों के लिए एक नोडल सीएपीएफ द्वारा भर्ती।
- दूसरा चरण: शेष पदों के लिए एसएससी भर्ती, जिसमें खाली पूर्व-अग्निवीर रिक्तियां भी शामिल हैं।

आयु में छूट:

- पहले बैच के लिए पांच साल और बाद के बैचों के लिए तीन साल।
- लड़ाकू कांस्टेबल (ट्रेड्समैन) के आमेलन के लिए ऊपरी आयु सीमा 30 से बढ़ाकर 35 वर्ष की गई है।

CAPF में प्रयोज्यता:

- सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, सशस्त्र सीमा बल और असम राइफल्स सहित सभी सीएपीएफ के लिए भर्ती नियमों में क्रमिक संशोधन।

शासन और सुरक्षा के लिए महत्व

रोजगार संबंधी चिंताओं को संबोधित करना: बढ़ा हुआ कोटा सीधे अग्रिम योजना की मुख्य आलोचना से निपटता है - सुनिश्चित पोस्ट-सर्विस रोजगार की कमी - इस प्रकार इसकी दीर्घकालिक स्थिरता को मजबूत करता है।

आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना: सीएपीएफ को अनुशासित, प्रशिक्षित और परिचालन रूप से अनुभवी जनशक्ति से लाभ होता है, जिससे प्रशिक्षण लागत कम होती है और तत्परता में सुधार होता है।

राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता : सार्वजनिक असंतोष और विरोध प्रदर्शनों का जवाब देकर, सरकार नीतिगत जवाबदेही और विश्वास-आधारित शासन का संकेत देती है।

नागरिक-सैन्य एकीकरण : यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे को मजबूत करते हुए आंतरिक सुरक्षा भूमिकाओं में अल्पकालिक सैन्य कर्मियों के सुचारू परिवर्तन की सुविधा प्रदान करता है।

चिंताएँ और चुनौतियाँ

खुली प्रतियोगिता पर प्रभाव: 50% आरक्षण CAPF में कम अवसरों के बारे में नागरिक उम्मीदवारों के बीच चिंताएँ पैदा कर सकता है।

परिचालन संतुलन: अल्पकालिक सैन्य रंगरूटों पर अधिक निर्भरता सीएपीएफ के भीतर कौशल और अनुभवों की विविधता को प्रभावित कर सकती है।

दीर्घकालिक अवशोषण सीमाएं: बड़ी संख्या में अग्निवीरों के सालाना सेवानिवृत्त होने के साथ, अकेले सीएपीएफ सभी को समाहित करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकते हैं, जिसके लिए व्यापक अंतर-मंत्रालयी रोजगार रणनीतियों की आवश्यकता होती है।

निष्कर्ष

सीएपीएफ में पूर्व-अग्निवीरों के लिए आरक्षण को बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने का निर्णय अग्निपथ योजना के कार्यान्वयन में एक व्यावहारिक सुधार का प्रतिनिधित्व करता है। यह लिखित परीक्षाओं के माध्यम से योग्यता-आधारित भर्ती को बनाए रखते हुए, एक विश्वसनीय पोस्ट-सर्विस मार्ग प्रदान करके सामाजिक-आर्थिक वास्तविकताओं के साथ सैन्य सुधार के उद्देश्यों को संतुलित करता है।

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न : सीएपीएफ में पूर्व-अग्निवीरों का बढ़ता अवशोषण अग्निपथ योजना के खिलाफ **2022** के विरोध प्रदर्शनों के दौरान उठाई गई चिंताओं को दूर करने का प्रयास कैसे करता है? मूल्यांकन करें कि क्या यह उपाय लंबे समय में पर्याप्त है। **(250 शब्द)**

भारत की संसद के हाल ही में संपन्न शीतकालीन सत्र में असाधारण रूप से उच्च विधायी उत्पादकता दर्ज की गई, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा ने क्रमशः 111 प्रतिशत और 121 प्रतिशत उत्पादकता हासिल की, जैसा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रेखांकित किया है। सत्र में प्रमुख सुधारोन्मुखी विधेयकों को पारित करने, राष्ट्रीय प्रतीकों और चुनाव सुधारों पर ठोस बहस और संसदीय शिष्टाचार पर चिंता शामिल थी। यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए, यह सत्र संसदीय कामकाज, शासन सुधारों और लोकतांत्रिक जवाबदेही के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है।

Winter Session concludes with over 100% productivity

The Hindu Bureau
NEW DELHI

The Winter Session of Parliament concluded on Friday as both Houses were adjourned *sine die* after the passage of key Bills, including one to replace the MGNREGA and others to allow the opening up of the civil nuclear sector for private sector and 100% FDI in Insurance.

Lok Sabha Speaker Om Birla said the Lower House recorded a productivity of 111% over 15 sittings, while Rajya Sabha Chairman C.P. Radhakrishnan, who presided over his first session after taking charge, said the Upper House achieved a productivity of 121%.

The Lok Sabha passed eight Bills, and 10 government Bills were introduced.

The Lok Sabha witnessed a debate to mark 150 years of the National Song *Vande Mataram*. Prime Minister Narendra Modi initiated the discussion and the Lower House discussed the subject for 11 hours and 32 minutes, with the participation of 65 MPs. The issue of electoral reforms was also discussed for approximately 13 hours, with the participa-



Om Birla

tion of 63 members.

In Rajya Sabha, 82 members participated in the discussion on *Vande Mataram*. On electoral reforms, 57 members participated. The Upper House passed eight Bills and adopted a Statutory Resolution regarding the Water (Prevention and Control of Pollution) Amendment Act, 2024, which saw overall participation of 212 MPs.

“Disruption created during yesterday’s (Thursday) sitting by the Opposition members by shouting slogans, displaying placards, disrupting the Minister replying to the discussion, tearing up papers and throwing them in the Well of the House showed conduct unbecoming of MPs. I earnestly hope that members would introspect and not repeat such unruly behaviour in future,” Mr. Radhakrishnan said.

प्रमुख मुद्दे और महत्व

1. विधायी उत्पादकता और शासन दक्षता

- 100 प्रतिशत से अधिक उत्पादकता विस्तारित बैठकों और निर्धारित समय के प्रभावी उपयोग को इंगित करती है, जो विधायी परिणाम पर जोर देने को दर्शाती है।
- ग्रामीण रोजगार गारंटी (मनरेगा का प्रतिस्थापन), असैन्य परमाणु क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोलने, और बीमा में 100% एफडीआई की अनुमति देने से संबंधित विधेयकों का पारित होना सामाजिक नीति, ऊर्जा सुरक्षा और पूंजी प्रवाह के लिए निहितार्थ के साथ एक सुधार-संचालित शासन दृष्टिकोण का संकेत देता है।

2. संसदीय विचार-विमर्श की गुणवत्ता

- वंदे मातरम (150 साल पूरे होने पर) और चुनाव सुधारों पर विस्तारित बहस केवल कानून बनाने से परे संसद की विचारशील भूमिका को प्रदर्शित करती है।
- दोनों सदनों में सांसदों की सक्रिय भागीदारी प्रतिनिधि लोकतंत्र के संवैधानिक आदर्शों के अनुरूप बहस की समावेशिता और मजबूती का सुझाव देती है।

3. संसदीय नेतृत्व की भूमिका

- इस सत्र की अध्यक्षता राज्यसभा के सभापति सी. पी. राधाकृष्णन ने की, जिसमें व्यवस्था, समय प्रबंधन और द्विदलीय कामकाज सुनिश्चित करने में पीठासीन अधिकारी के महत्व पर प्रकाश डाला गया।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वंदे मातरम पर बहस की शुरुआत संसदीय लोकतंत्र के भीतर कार्यपालिका की एजेंडा-निर्धारण भूमिका को रेखांकित करती है।

4. संसदीय आचरण और लोकतांत्रिक मानदंड

- विपक्षी सदस्यों द्वारा नारेबाजी और सदन के बीचोंबीच में प्रवेश करने सहित व्यवधान संसदीय मर्यादा के क्षरण के बारे में चिंता पैदा करता है।
- इस तरह का आचरण विधायी दक्षता और सार्वजनिक विश्वास को प्रभावित करता है, जिससे संसदीय नैतिकता, आचार संहिता और अनुशासनात्मक तंत्र के प्रभावी उपयोग से संबंधित सुधारों की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

5. संघीय और पर्यावरणीय आयाम

- जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 2024 पर वैधानिक संकल्प को अपनाना, पर्यावरण विनियमन के साथ विकास को संतुलित करने में संसद की भूमिका को दर्शाता है - जो शासन और संघीय समन्वय के लिए बढ़ती प्रासंगिकता का क्षेत्र है।

निष्कर्ष

शीतकालीन सत्र एक उच्च उत्पादकता वाले संसदीय सत्र के रूप में सामने आता है, जो विधायी आउटपुट को ठोस बहस के साथ जोड़ता है, जो भारत के लोकतांत्रिक ढांचे में संसद की केंद्रीयता को मजबूत करता है। हालांकि, बार-बार आने वाले व्यवधान संरचनात्मक और व्यवहारिक चुनौतियों को रेखांकित करते हैं जिन्हें संसदीय संस्थानों की गरिमा और प्रभावशीलता को बनाए रखने के लिए संबोधित किया जाना चाहिए।

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न : निम्नलिखित में से कौन सा संसद की संवैधानिक भूमिका को सबसे अच्छी तरह से समझाता है जैसा कि शीतकालीन सत्र में परिलक्षित होता है?

- (a) केवल कानून बनाना
- (b) प्रश्नकाल के माध्यम से कार्यकारी नियंत्रण
- (c) विचारशील और प्रतिनिधि लोकतंत्र
- (d) संघीय विवाद समाधान

उत्तर : (c)

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न : भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करने में चुनाव सुधारों पर संसदीय बहस के महत्त्व पर चर्चा कीजिए।

एक महत्वपूर्ण फैसले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि सुरक्षात्मक कानूनों के अस्तित्व के बावजूद भारत में बाल तस्करी और व्यावसायिक यौन शोषण एक "गहरी परेशान करने वाली वास्तविकता" बनी हुई है। इस फैसले ने न केवल अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम के तहत दोषसिद्धि को बरकरार रखा, बल्कि बाल तस्करी के मामलों में सबूतों की सराहना करने के लिए महत्वपूर्ण न्यायिक सिद्धांतों को भी निर्धारित किया, विशेष रूप से नाबालिग पीड़ितों की गवाही के संबंध में।

Child trafficking a deeply disturbing reality, says SC

SC judgment emphasises that courts must not disbelieve the testimony of a trafficked child just because of minor inconsistencies in her evidence; says she must be treated as an injured witness

Krishnadas Rajagopal
NEW DELHI

The Supreme Court, in a judgment on Friday, observed that child trafficking and commercial sexual exploitation of children by organised cartels is a "deeply disturbing reality" in India which continues to flourish despite protective laws. The court said child trafficking networks have a complex and layered structure which operate at various levels of recruiting, transporting, harbouring, and exploiting minor victims.

The judgment, which laid down guidelines for appreciating evidence in child trafficking cases, said courts must not disbelieve the testimony of a trafficked child just because of minor inconsistencies in her evidence.

"Such organised crime activities operate as apparently independent verticals whose insidious intersections are conveniently veiled through subterfuge and deception to hoodwink innocent victims," a Bench of Justices Manoj Misra and Joymalya Bagchi said.

Judicial sensitivity

Courts have been asked to bear in mind several key points while recording the evidence of a minor trafficking victim

- The child's socio-economic and cultural vulnerability, especially if from a marginalised or backward community
- Organised crime networks operate through complex, layered structures that often mislead minors; victims should not be faulted for failure to protest promptly
- Judicial consideration of a minor's testimony must be sensitive and avoid secondary victimisation
- A conviction can rest on the sole testimony of the victim if it is credible and convincing
- A trafficking victim's testimony deserves the same weight as that of an injured witness

A victim's sole testimony must suffice if her version appeared to be credible and convincing. A trafficked child must not be treated as an accomplice by the courts. "Her deposition is to be given due regard and credence as that of an injured witness," the court directed.

Justice Bagchi, who authored the judgment, termed child trafficking and sexual exploitation as an offence that struck at the very foundations of dignity and bodily integrity.

The judgment concerned a minor who was forcibly pushed into illicit sexual intercourse by a

gang of traffickers in Bengaluru. Her persistent refusal to consent had led her to be confined in a rental apartment, until she was rescued by the police in November 2010.

The top court, while upholding the conviction of the gang members under the Immoral Traffic (Prevention) Act, said the case laid bare the "moral and material abandonment" of a child whom the state was constitutionally obliged to protect from harm's way.

Justice Bagchi said courts must not discard a trafficked victim's version as improbable or "against ordinary human conduct"

solely on the ground of her failure to promptly protest against the "ostensibly innocuous yet ominous agenda of the trafficker".

"Diffused and apparently disjoint manner in which the crime verticals operate in areas of recruitment, transportation, harbouring and exploitation make it difficult, if not impossible, for the victim to narrate with precision and clarity the interplay of these processes..." Justice Bagchi observed.

Recognise vulnerability

In the present case, the victim's testimony about the topography of the rented apartment was rebutted by two prosecution witnesses, prompting the defence to attempt to discredit her evidence.

The Bench underscored that courts must bear in mind, while examining a victim, her "inherent socio-economic and, at times, cultural vulnerability when the minor belongs to a marginalised or socially and culturally backward community".

Judicial appreciation of the victim's evidence must be marked by sensitivity and realism, it said.

सर्वोच्च न्यायालय की प्रमुख टिप्पणियाँ

- साक्ष्य के प्रति पीड़ित-केंद्रित दृष्टिकोण: न्यायालय ने स्पष्ट किया कि तस्करी किए गए बच्चे की गवाही पर केवल छोटी-मोटी विसंगतियों के कारण अविश्वास नहीं किया जा सकता है। आघात, भय, लंबे समय तक कारावास और सामाजिक-आर्थिक भेद्यता अक्सर सटीक स्मरण को खराब करती है।

- पीड़ित बच्चे की स्थिति: तस्करी का शिकार बच्चा साथी नहीं है। उसकी गवाही एक घायल गवाह के समान वजन की हकदार है। यदि विश्वसनीय और ठोस है, तो दोषसिद्धि के लिए एकमात्र गवाही पर्याप्त है।
- तस्करी नेटवर्क की प्रकृति: यह निर्णय तस्करी को एक संगठित अपराध के रूप में मान्यता देता है, जिसमें स्तरित कार्यक्षेत्र- भर्ती, परिवहन, आश्रय और शोषण - एक विस्तृत और भ्रामक तरीके से संचालित होते हैं, जिससे पीड़ितों द्वारा कथन स्वाभाविक रूप से खंडित हो जाता है।
- न्यायिक जांच में संवेदनशीलता: अदालतों को बाल पीड़ितों, विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों की सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक भेद्यता को ध्यान में रखना चाहिए। साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय न्यायिक यथार्थवाद और सहानुभूति आवश्यक है।

संवैधानिक और कानूनी महत्व

- बच्चों को शोषण से बचाने के लिए राज्य के संवैधानिक दायित्व की पुष्टि करके अनुच्छेद 21 (जीवन और गरिमा का अधिकार) को सुदृढ़ करता है।
- यह अनुच्छेद 15(3) और अनुच्छेद 39(ई) और (एफ) की भावना को मजबूत करता है, जो बच्चों के लिए विशेष सुरक्षा को अनिवार्य करता है।
- बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (सीआरसी) जैसे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के तहत भारत की प्रतिबद्धताओं के साथ घरेलू न्यायशास्त्र को संरेखित करता है, भले ही स्पष्ट रूप से उद्धृत न किया गया हो।

आगे की राह

- आघात-सूचित प्रक्रियाओं में पुलिस, अभियोजकों और न्यायाधीशों की क्षमता निर्माण।
- बाल संरक्षण कानूनों के तहत पुनर्वास तंत्र को मजबूत करना।
- कानून प्रवर्तन, न्यायपालिका और बाल कल्याण संस्थानों के बीच बेहतर समन्वय।
- स्रोत पर भर्ती नेटवर्क को बाधित करने के लिए सामुदायिक स्तर की सतर्कता।

निष्कर्ष

सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाल तस्करी के मामलों में पीड़ित-संवेदनशील और अधिकार-आधारित आपराधिक न्याय दृष्टिकोण की दिशा में एक निर्णायक बदलाव का प्रतीक है। संगठित तस्करी की जटिल प्रकृति और बाल पीड़ितों के जीवित आघात को पहचानकर, यह निर्णय गरिमा, न्याय और करुणा के संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करता है। यह एक स्पष्ट संकेत भेजता है कि प्रक्रियात्मक कठोरता को वास्तविक न्याय को नहीं हराना चाहिए, खासकर जब सबसे कमजोर लोग दांव पर हों।

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: भारत में बाल तस्करी का मुकाबला करने में राज्य और न्यायपालिका के संवैधानिक दायित्वों पर चर्चा करें। तस्करी किए गए बच्चे की गवाही की सराहना करने में न्यायिक संवेदनशीलता बाल संरक्षण कानूनों के प्रभावी प्रवर्तन में कैसे योगदान करती है? (250 शब्द)

हैदराबाद एक संरचनात्मक परिवर्तन के शिखर पर है क्योंकि तेलंगाना सरकार नाइट टाइम इकोनॉमी (एनटीई) ढांचे को लागू करने की तैयारी कर रही है। छिटपुट और त्योहारों द्वारा संचालित रात्रिचर वाणिज्य से आगे बढ़ते हुए, नीति का उद्देश्य क्षेत्र-आधारित विनियमन, बेहतर शहरी सेवाओं और उन्नत सुरक्षा तंत्र के माध्यम से 24x7 आर्थिक गतिविधियों को संस्थागत बनाना है। यह पहल तेलंगाना के विजन 2047 के मूलभूत स्तंभ के रूप में स्थित है, जो 3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की आकांक्षा रखता है।



Taking a step closer towards awakening Hyderabad nightlife

The city is inching towards a 24/7 future as the government prepares to roll out proposals under 'Night Time Economy' to make late-night business a year-round reality. The policy seeks to cut bureaucratic red tape, extend public transport and strengthen safety and sanitation, projecting a ₹25000-crore economic boost and creation of lakhs of jobs by 2032. Senior Nandan reports on how this initiative offers an early glimpse of Telangana's ambitious \$3 trillion economy envisioned under Vision 2047.

Glenn's eyes keep drifting back to the road as he walks to the bar at a mid-range eatery. It is 11.30 p.m. on a weekday and the traffic that keeps around Durgam Chattram in Hyderabad never quite passes, and every dining vehicle draws a glance. "People keep coming here throughout the night," he says, glancing up and down the street, tracking both customers and other busier means. "I usually wait for 1-2 m. When the police vehicle comes around midnight, it creates panic, for the diners as well as for us," he adds.

For a late hour, the place remains unusually busy. Cars and motorcycles slow down, then surge ahead, jolting over the dozens of rattle strips—some a heavy hand, others light from officers, shopping malls and high-rise apartments. The street is a soft yellow glow. On the roadside, the acid smoke of cooking hangs in the air. Bikes and cars clang, child cries and the pungent heat hits the nostrils. A car pulls over. Three young men step out, hunch their shoulders against the smoke and heat, fill their hands with their checks and for them, the night is a blur.

Glenn adds a thick bubble tube from the fry, cracks it open and tips out the grease, spicy, reddish red chili sauce three disposable plates. Priced at ₹200, the dish draws a steady stream of customers, some of them perched on plastic chairs and tables by the road while others eat inside their cars.

Glenn, who has been working in the IT sector for 15 years, never dines out every night, working quickly and always keeping on the move for the town of the police vehicle. For years, Hyderabad's night life has thrived on caution and chance, but this scene may change by the new year. The street of police is now in the Chattram area, which is a police commercial area of Hyderabad. In a bid to maintain streetlights, the Telangana government is to roll out a clutch of proposals under what it calls the Night Time Economy (NTE).

"We will start NTE from January, initially on select stretches in Old City, Secunderabad and Cyberabad," says Javed Raza, Special Chief Secretary of the State government. Night economy itself is not new to Hyderabad. During the month-long Ramzan, three days of

Shivaratni or 30 days of Muharram, the city comes alive after dark, meeting extraordinary business opportunities. Restaurants often start the countdown to Ramzan for the midnight availability of halwa, iconic restaurants such as all hand-drawn food in Agartala, Nagpur and Bhopal and Naya Pal, along with countless others in the inner lanes, have long opened post official closing hours, often in a car and mouse game with police patrol.

Unlike these seasonal bursts of activity, the new initiative aims to make late-night business a year-round reality, cutting through bureaucracy and transforming it into a legitimate, organised opportunity. "The new 24/7 framework is completely different. It is more based, not permission-based. Once an area is declared a Night Time Economy zone, every business inside it can operate late hours automatically—no permits, no licences, no inspections, no NOCs, no department hopping," explains Nandan Chatterjee, founder of the Centre for Liberty, who helped draft the policy.

No interference "The nation 24/7 initiative launched under KTR, leader and former industrial minister, K. T. Rama Rao collapsed because it relied on the old model of license, permits and bureaucratic gatekeeping. Businesses had to navigate a maze of approvals, which killed the reform before it

even took off. Under the new system, there is no permit or licence. Government officials will stay away from business operations. The government role will be limited," he added. The policy identifies four key factors essential for permit-free night zones. "Economic density was the first criterion. Areas with a high concentration of commercial establishments, like Old City and Financial District, were prioritised because they naturally support late-night economic activity. Second, zones that already attract people at night—food streets, malls, multiplexes, restaurants and entertainment corridors—were chosen since they can be activated quickly without generating new demand," Chatterjee points out.

Old City, one of Hyderabad's oldest neighbourhoods with a dense mix of offices and residences, has a secret ultra high street compared to other parts of the city. According to Crowdfunder of Real Estate Developers' Association of India (REDAI), which tracks property values, the rental rates have reached 106 per square foot, marking a 15% year-on-year growth, driven by a high demand-supply ratio, with Hyderabad, Pune and Mumbai playing key roles in the surge. These high rents turn the food business into a high-stakes gamble.

Spillover for choice Inside Sarva Knowledge City, office goers and occasional visitors are spotted for choice. Whisking Samosa, Biryani, Rasam, Sabzi, Tandoori, Flavourful, and many more, for an hour, with the likes of Starbucks, Third Wave Coffee, and others. But the last order is still called between 11 p.m. and 11.30 p.m., just as scores of IT employees log off, looking for a ride, a snack, a cup of chai or a few minutes of conversation before heading home.

It is this socio-economic demand that the 24/7 policy seeks to address. The NTE is projected to give Hyderabad's economy a boost, with contributions expected to grow from ₹5,500 crore in 2022 to ₹24,000 crore by 2032, representing a compounded annual growth rate of 20.8%. The expansion is also expected to generate 2.5-3 lakh jobs by 2031 across hospitality, retail, entertainment, transport and security.

People who visit Park want to see it at night. The 18th Floor should be experienced both during the day and at night. Tourists in Hyderabad want the same," says A. Shankar Rao, managing director of Cafe Bharat. He breaks down the restaurant's economic by the hour: "From morning to afternoon, we do about 25% of our business. From afternoon to night, it's 75%. But we still pay salaries to cover both periods. About 80% of the business happens in the last eight hours, roughly 10% per hour. If operating hours are extended, we will benefit and customers will also have more choices. It will be very beneficial for businesses."

He adds that parking and staffing pose minor challenges, but are manageable nonetheless. "To coordinate this ecosystem, the city will appoint a Night czar, an independent authority whose job is not to control businesses but to grow the night economy by reducing government interference and ensuring smooth coordination between departments. The additional tax revenue generated by a thriving night economy, across hospitality, retail, transport, entertainment and logistics, will more than cover the cost of extended police presence, sanitation, lighting and public transport," says Chatterjee.

The Vision 2047 document outlines the role of the Night Commissioner and the reform of the transportation policy. "The State establishes a single empowered office coordinating safety, sanitation and mobility to enable swift decisions," Municipal administration will set up NTE Zones—Gachibowli, Madhapur, Jubilee Hills, HITE, Tarnaka, Old City and Airport Financial District—then expand citywide to achieve seamless 24/7 operations.

Outside Park restaurant in the Financial District, food delivery is the mainstay. The delivery office crowd waiting by. How much money do these people make? ₹10,000 to ₹15,000 in 10 orders between noon and 1 a.m. It is a good month, I earn up to ₹10,000. I deliver at least 20 orders after midnight since many restaurants stay open, and I can drive at 80-100 kmph," says the 25-year-old from SBI, who works for a food-delivery app.

While keeping the city's food economy moving, NTE is also a consumer. "I grab a snack at midnight before heading to bed and having dinner at home," he says.

Hyderabad, in addition to attracting a large IT workforce, is home to lakhs of skilled and gig workers who keep the city humming. Rana Raza, who moved to the city 15 years ago and now works from the 18th Floor, says: "Most of these people don't live here. They come here to have food and drinks."

Challenges of night economy On this short stretch of sidewalk, 62 food kiosks cater to the cravings of home-sick workers with Regional Chicken Polka, Noodles, Ramen, Chole Bhat, Masala Paratha, Poha, Idli, Mutton and more. But as midnight approaches, the lively sidewalk slowly turns into a trash-strewn corridor, a reminder of the challenges that come with a thriving night economy.

Hygiene, sanitation, safety, and waste disposal remain among the key challenges to this ambitious policy. To address them, the plan focuses on urban design improvements with focus on clean public toilets, strategically placed waste bins, and dedicated night sanitation vans. It also includes extending Metro and State-run bus services till 2 a.m., complemented by night shuttle services and dedicated auto and taxi stands. Safety measures go beyond surveillance, with Park, Frisco, and other night hubs, street lighting, CCTV coverage and SOS systems.

Part of the city plan these systems change, the night continues to burn with life. Outside Cafe Bharat near Yashwantrao Chavan Park, a couple poses for their wedding album at 11 p.m., the coloured lights of TADA, an innovation incubator and business incubator in Hyderabad, flickering behind them while scores of visitors play past. Along with their photographer friends, they eventually walk into the cafe.

A little further along, on Tarnaka Road, a group of friends wait for midnight to cut a cake and toast to the night. At 11.55 p.m., at Road CXN in Banjara Hills, a voice calls out "Last order" just as the clock strikes 12. Come January, these two divided worlds may finally be a thing of the past, as Hyderabad moves closer to a seamless 24/7 night economy.

रात्रिकालीन अर्थव्यवस्था नीति की मुख्य विशेषताएं

- ज़ोन-आधारित विनियमन
- नामित रात्रि समय अर्थव्यवस्था क्षेत्र व्यवसायों को व्यक्तिगत लाइसेंस, परमिट या एनओसी के बिना चौबीसों घंटे काम करने की अनुमति देते हैं।
- यह अनुमति-आधारित शासन से विश्वास-आधारित विनियमन में बदलाव का प्रतीक है, जिससे नौकरशाही घर्षण कम हो गया है।

लक्षित शहरी भूगोल

- हाईटेक सिटी, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, ओल्ड सिटी, सिकंदराबाद और बंजारा-जुबली हिल्स जैसे उच्च आर्थिक-घनत्व वाले गलियारों में प्रारंभिक रोलआउट।
- ये क्षेत्र पहले से ही आईटी रोजगार, पर्यटन, फूड स्ट्रीट और मनोरंजन केंद्रों के कारण रात के समय की मांग को प्रदर्शित करते हैं।

संस्थागत नवाचार

- सूक्ष्म प्रबंधन व्यवसायों के बिना पुलिसिंग, स्वच्छता, परिवहन और प्रकाश व्यवस्था के समन्वय के लिए एक नाइट ज़ार / नाइट कमिश्नर का निर्माण।
- लंदन और एमस्टर्डम जैसे शहरों में देखी गई वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को दर्शाता है।

आर्थिक और रोजगार प्रभाव

अनुमानित आर्थिक योगदान:

- ₹8,500 करोड़ (2025) → ₹26,000+ करोड़ (2032)
- 20% से अधिक का सीएजीआर

रोजगार सृजन:

- 2031 तक हॉस्पिटैलिटी, रिटेल, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्ट, सिक्योरिटी और गिग प्लेटफॉर्म पर 2.1-2.4 लाख नौकरियां।
- विशेष रूप से प्रवासियों, डिलीवरी श्रमिकों, रेहड़ी-पटरी वालों और अनौपचारिक सेवा प्रदाताओं के लिए समावेशी शहरी आजीविका का समर्थन करता है।

यह भारत के व्यापक उद्देश्यों के अनुरूप है:

- श्रम-गहन विकास
- सेवा क्षेत्र का विस्तार
- अनौपचारिक आर्थिक गतिविधियों का औपचारिकीकरण
- शासन और शहरी नियोजन आयाम
- व्यापार करने में आसानी
- "लाइसेंस राज" को समाप्त करता है जिसने पहले की 24x7 पहलों को कमजोर कर दिया था।
- पूर्वानुमानित नियम अनुपालन लागत को कम करते हैं और निजी निवेश को प्रोत्साहित करते हैं।

शहरी बुनियादी ढांचे का विस्तार

- मेट्रो और राज्य बस सेवाओं का विस्तार रात 2 बजे तक
- रात्रि स्वच्छता दस्ते, स्वच्छ सार्वजनिक शौचालय, अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली।
- स्मार्ट लाइटिंग, सीसीटीवी कवरेज, एसओएस सिस्टम और समर्पित टैक्सी/ऑटो स्टैंड।

लिंग-संवेदनशील शहरी डिजाइन

- गुलाबी गश्ती, महिलाओं के लिए केवल रात्रि केंद्र और सुरक्षित गतिशीलता गलियारों की तैनाती।

- अंधेरा होने के बाद महिलाओं के कार्यबल की भागीदारी और शहर के अधिकार को बढ़ाता है।
- सामाजिक और पर्यावरणीय चुनौतियाँ
- अपने वादे के बावजूद, नाइट टाइम इकोनॉमी कई चिंताएँ पैदा करती है:

सार्वजनिक स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन

- नाइट फूड सड़कों को सख्त प्रवर्तन के बिना स्वच्छता हॉटस्पॉट बनने का जोखिम है।

कानून और व्यवस्था

- उत्पीड़न या नैतिक पुलिसिंग के बिना निरंतर पुलिसिंग की आवश्यकता है।

शहरी असमानता

- लाभ समृद्ध क्षेत्रों में केंद्रित रह सकते हैं जब तक कि समान रूप से विस्तारित न किया जाए।

पर्यावरणीय बाह्यताएं

- ध्वनि प्रदूषण, प्रकाश प्रदूषण और बढ़ी हुई ऊर्जा खपत को विनियमित किया जाना चाहिए।
- ये चुनौतियाँ मजबूत नगरपालिका क्षमता और अंतर-विभागीय समन्वय की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं।

निष्कर्ष

नाइट टाइम इकोनॉमी पहल शहरी शासन में एक आदर्श बदलाव का प्रतिनिधित्व करती है, जो भारत के प्रतिबंधात्मक विनियमन से सुविधाजनक शासन कला में परिवर्तन का संकेत देती है। यदि संस्थागत अनुशासन, नागरिक जवाबदेही और समावेशिता के साथ लागू किया जाता है, तो हैदराबाद का 24x7 मॉडल पूरे भारत में महानगरीय सुधार के लिए एक टेम्पलेट बन सकता है। विस्तारित व्यावसायिक घंटों से अधिक, यह इस गहरी मान्यता को दर्शाता है कि आधुनिक शहरों को प्रतिस्पर्धी, समावेशी और विश्व स्तर पर प्रासंगिक बने रहने के लिए लगातार काम करना चाहिए - जो भारत की दीर्घकालिक आर्थिक और विकासात्मक महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए एक शर्त है।

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: नाइट टाइम इकोनॉमी (एनटीई) का उद्भव विश्वास-आधारित शहरी शासन और समावेशी आर्थिक विकास की ओर बदलाव को दर्शाता है। हैदराबाद के प्रस्तावित **24x7** अर्थव्यवस्था मॉडल के संदर्भ में चर्चा कीजिए। **(150 शब्द)**

भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति के हालिया मिनटों में एक असामान्य व्यापक आर्थिक चिंता का पता चलता है: भारत में मुद्रास्फीति अत्यधिक निम्न स्तर पर गिर गई है। अक्टूबर 2025 में हेडलाइन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन 0.3% तक कम हो रही है, जो 4% लक्ष्य से कम है और यहां तक कि कम टॉलरेंस बैंड को भी तोड़ रही है, MPC सदस्यों ने उच्च मुद्रास्फीति से नहीं, बल्कि विकासशील अर्थव्यवस्था में लंबे समय तक डिप्लेयर के साथ जुड़े जोखिमों को चिह्नित किया है।

‘Too low an inflation a cause for concern’

Prevailing low inflation will squeeze profit margins, increase real value of debt and interest rates for private sector, says MPC's external member

Lalatendu Mishra
MUMBAI

Although low inflation rate and high growth led the Monetary Policy Committee (MPC) to reduce repo rate by 25 basis points (bps) earlier this month to support growth, the drastic fall in inflation numbers remained a cause for concern, the minutes of the MPC released by the Reserve Bank of India (RBI) on Friday indicate.

“The current inflation rate is actually too low, breaching the lower bound in the flexible inflation targeting regime, especially if precious metals like gold are excluded. Besides, too low an inflation rate is not healthy for a developing country like India, suggesting a demand deficit,” external MPC member Nagesh Kumar wrote.

He said inflation not only continued to remain benign, the headline CPI too declined further to 0.3% in October 2025, largely driven by decreasing food prices. “It is in contrast to FY25: Q2, when the growth was slowing, but inflation was at relatively high levels,” he pointed out.

Stating that inflation had continued to undershoot forecasts, external MPC member Saugata Bhattacharya said while the low prints had largely emanated from a small set of components, the broader basket of “underlying” inflation too was likely to undershoot the inflation target for many months.



Dribbling down: Headline CPI declined further to 0.3% in October 2025, largely driven by decreasing food prices. SUSHIL KUMAR VERMA

ket of “underlying” inflation too was likely to undershoot the inflation target for many months.

“In addition, there is little to signal a risk of potential overheating of capacity even if growth momentum were to sustain. Household inflation expectations remain well anchored and have responded to the recent sharp drop in inflation,” he stated.

External member Prof. Ram Singh said in his statement that the prevailing low inflation would squeeze profit margins and increase the real value of debt and interest rates for the private sector.

“Disinflationary expectations running across several quarters can dampen and defer private-sector investment even in the short run. As MSMEs’ businesses operate in highly competitive markets and have limited ability to raise prices through the market power channel but the wages tend to be downward

sticky, low inflation is detrimental to their interests as well,” he emphasised.

Deputy Governor Poonam Gupta stated that inflation had been below the 4% target for the last nine months averaging 2.3% and was likely to remain well contained for at least nine more months. “The average inflation for 2025-26 is projected to be 2.0%, down by 60 bps from the October policy.

The most crucial recent development from the perspective of monetary policy has been the faster than anticipated moderation in CPI headline inflation,” she wrote. “Going ahead, good agricultural production, low food prices and exceptionally benign international commodity price outlook suggest that headline inflation for the full year (2025-26) is likely to be around 2%, half of what was projected at the beginning of the year, RBI Governor Sanjay Malhotra wrote in his statement.

क्यों "बहुत कम मुद्रास्फीति" एक चिंता का विषय है

मांग घाटे का संकेत

- लगातार कम मुद्रास्फीति कमजोर कुल मांग को इंगित करती है, खासकर जब एकबारगी आपूर्ति के झटके के बजाय व्यापक-आधारित मूल्य मॉडरेशन द्वारा संचालित होती है।

- एमपीसी सदस्यों ने कहा कि यहां तक कि "अंतर्निहित मुद्रास्फीति" भी लक्ष्य को कम कर रही है, जो खपत में संरचनात्मक नरमी का सुझाव देती है।

निवेश और विकास पर प्रभाव

- कम मुद्रास्फीति वास्तविक ब्याज दर को बढ़ाती है, यहां तक कि 25 बीपीएस रेपो दर में कटौती के बाद भी।
- उच्च वास्तविक उधार लागत हो सकती है:
- निजी निवेश को हतोत्साहित करें
- क्षमता विस्तार में देरी
- विशेष रूप से एमएसएमई के बीच ऋण की मांग कम करें

लाभप्रदता और एमएसएमई तनाव

- फर्मों को संकुचित लाभ मार्जिन का सामना करना पड़ता है क्योंकि उत्पादन की कीमतें स्थिर हो जाती हैं जबकि मजदूरी नीचे की ओर चिपचिपी रहती है।
- सीमित मूल्य निर्धारण शक्ति वाले एमएसएमई असमान रूप से प्रभावित होते हैं, जिससे रोजगार की संभावनाएं खराब हो जाती हैं।

ऋण गतिशीलता

- अवस्फीति बकाया ऋण के वास्तविक मूल्य को बढ़ाती है, जिससे परिवारों और फर्मों के लिए पुनर्भुगतान का बोझ बढ़ जाता है।
- यह बैलेंस शीट को कमजोर कर सकता है और वित्तीय तनाव को बढ़ा सकता है।

मौद्रिक नीति निहितार्थ

- RBI एक फ्लेक्सिबल इम्प्लेशन टारगेटिंग (FIT) फ्रेमवर्क (4% $\pm$ 2%) के तहत काम करता है।
- वर्तमान मुद्रास्फीति:
- लगातार नौ महीने लक्ष्य से नीचे
- वित्त वर्ष 2025-26 अनुमानित औसत: ~2%
- यह स्थिति एक नीति दुविधा पैदा करता है:
- आक्रामक सहजता जोखिम भविष्य की संपत्ति बुलबुले
- निष्क्रियता जोखिम अपस्फीति की उम्मीदों को बढ़ा देती है

जैसा कि एमपीसी सदस्यों द्वारा हाइलाइट किया गया है, **एंकर्ड मुद्रास्फीति की उम्मीदें**, वांछनीय होने के बावजूद, सीमित मूल्य निर्धारण शक्ति और कम मांग की गति का संकेत भी दे सकती हैं।

व्यापक संरचनात्मक कारक

- खाद्य मूल्य प्रभुत्व
 - तीव्र मॉडरेशन द्वारा संचालित:
 - अच्छा कृषि उत्पादन
 - कम खाद्य कीमतें

- खाद्य पदार्थों की कीमतें सामान्य होने के बाद मुद्रास्फीति में उतार-चढ़ाव के बारे में चिंता जताई।

वैश्विक संदर्भ

- असाधारण रूप से सौम्य अंतरराष्ट्रीय कमोडिटी की कीमतों ने अवस्फीतिकारी दबावों को मजबूत किया है।
- हालांकि, भू-राजनीतिक या आपूर्ति-श्रृंखला के झटके के कारण यह उलट सकता है।

विकास-मुद्रास्फीति डिस्कनेक्ट

- भारत अल्ट्रा-लो मुद्रास्फीति के साथ उच्च विकास प्रदर्शित करता है, जो पारंपरिक फिलिप्स कर्व अपेक्षाओं से एक विचलन है।
- सुझाव देता है कि विकास असमान, क्षेत्र-विशिष्ट या गैर-उपभोग-नेतृत्व वाला हो सकता है।

निष्कर्ष

जबकि कम मुद्रास्फीति को पारंपरिक रूप से सकारात्मक के रूप में देखा जाता है, अत्यधिक कम और लंबे समय तक मुद्रास्फीति भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर व्यापक आर्थिक जोखिम पैदा करती है। यह निवेश को दबा सकता है, एमएसएमई पर दबाव डाल सकता है और वास्तविक ऋण का बोझ बढ़ा सकता है, जिससे सतत विकास कमजोर हो सकता है। एमपीसी की चिंता एक संतुलित व्यापक आर्थिक रणनीति की आवश्यकता को रेखांकित करती है, जहां मौद्रिक सहजता को राजकोषीय समर्थन, मांग प्रोत्साहन और मूल्य स्थिरता को अस्थिर किए बिना खपत और निवेश को पुनर्जीवित करने के लिए संरचनात्मक सुधारों द्वारा पूरक किया जाता है। मुद्रास्फीति को केवल कम करने के बजाय लक्ष्य के करीब बनाए रखना भारत के दीर्घकालिक आर्थिक लचीलेपन के लिए महत्वपूर्ण है।

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न : विकासशील अर्थव्यवस्था में बहुत कम मुद्रास्फीति भी चिंता का कारण है। हाल ही में एमपीसी की टिप्पणियों के संदर्भ में, भारत के विकास और निवेश संभावनाओं के लिए लंबे समय तक कम मुद्रास्फीति के प्रभावों की जांच करें।

The significance of a strong defence industrial base

India's aspiration to become a developed nation by 2047 rests not only on social and economic transformation but also on the strength of its strategic capabilities. Among these, the defence industrial base occupies a pivotal role. For far too long, the country's defence manufacturing ecosystem has remained constrained by restrictive policies, resulting in limited private participation and excessive reliance on imports. Domestic private industries were not allowed in this sector but there were imports, without compunction, from private manufacturers from across the world. The result was a structural vulnerability that affected both economic potential and national security.

A shift after reforms

But there has been a significant shift in recent years. There has been an opening up to the private sector, liberalised foreign direct investment norms, corporatisation of the Ordnance Factory Board, and a progressive expansion of the list of arms and armaments to be procured under the 'Make' procedure apart from a pro-active promotion of innovation, which have all contributed to rapid progress. Defence production has increased and exports have grown exponentially, now reaching more than 80 countries.

These trends signal a maturing ecosystem that is increasingly capable of meeting domestic requirements while also contributing to global supply chains.

The evolving global security landscape, marked by conflicts in Europe, West Asia and Asia, has exposed the fragility of international peace and the risks of supply-chain disruptions. Nations with robust domestic defence industries have proved to be more resilient. For India, which faces persistent challenges along its borders and in the maritime domain, self-reliance



Rajiv Gauba
is Member, NITI Aayog

In an evolving global security landscape, India's security and economic ambitions demand nothing less

in defence is not only desirable but also indispensable.

At the same time, shifting geopolitical dynamics are opening up new possibilities. Europe's renewed emphasis on defence spending, the saturation of traditional suppliers, and growing demand for cost-effective and reliable platforms create opportunities that India is well-positioned to capture. The country's strategic geography in the Indian Ocean Region and its expanding diplomatic profile further strengthen its potential to emerge as a credible supplier of defence equipment.

Simplify procedures

But realising this potential will require sustained focus on reforms. Regulatory complexities continue to hinder private-sector participation, especially for micro, small and medium enterprises and startups. Export licensing, joint ventures and technology-transfer approvals need to be speeded up. Long-term demand projections will give the private sector the confidence to make large investments. The pathway to achieving India's stated ambition of ₹50,000 crore in defence exports by 2029 will require simplifying procedures and ensuring policy continuity.

The role of the Defence Research and Development Organisation (DRDO) also needs to evolve. The DRDO has been instrumental in building India's strategic capabilities, but the next phase demands a sharper division of responsibilities. Frontier research must remain its core focus, while production, scaling and commercialisation should increasingly shift to industry, public and private. Such an approach aligns with global best practices and will strengthen competitiveness.

A dedicated, professionally staffed export facilitation agency would streamline outreach

and provide a single-window interface for global partners. It will also help overcome the challenges arising from fragmented institutional arrangements across Ministries and the resultant coordination issues.

Key steps to take

Equally important is the need to overhaul financial, testing and certification frameworks. Indian manufacturers often face challenges in securing competitive credit lines, meeting excessively stringent domestic standards and conducting trials within reasonable timelines.

Establishing specialised export financing instruments, expanding integrated testing facilities and adopting international certification protocols can dramatically improve competitiveness. A more proactive use of lines of credit, government-to-government agreements, and long-term service commitments would further enhance India's credibility in a market dominated by established players.

Defence exports are not merely a commercial undertaking. They signify technological maturity, strategic reliability and the emergence of a nation as a major actor in the international security architecture. Strengthening the defence industrial base is essential not only for reducing import dependency but, equally, for generating high-skilled employment, and enhancing geopolitical leverage.

The progress in recent years is encouraging. What is required now are consistent efforts to deepen reforms and build an ecosystem that encourages innovation and investments. India's security and economic ambitions demand nothing less.

The pursuit of a strong defence industrial base is not just a strategic necessity. It is a defining step toward India's emergence as a confident, capable and influential global power.

GS Paper 2 : International Relations

UPSC Mains Practice Question : एक मजबूत रक्षा औद्योगिक आधार एक रणनीतिक आवश्यकता और एक आर्थिक अवसर दोनों है। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों और विकासात्मक आकांक्षाओं के संदर्भ में इस कथन की आलोचनात्मक जांच कीजिए। (150 शब्द)

संदर्भ :

विजन 2047 के तहत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने की भारत की आकांक्षा न केवल आर्थिक विकास और सामाजिक समावेशन पर बल्कि रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी समान रूप से टिकी हुई है। इस संदर्भ में, भारत के रक्षा औद्योगिक आधार को मजबूत करना एक मुख्य राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में उभरा है। जैसा कि नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने रेखांकित किया है, आयात निर्भरता को कम करने, वैश्विक अस्थिरता के बीच लचीलापन बढ़ाने और भारत को एक विश्वसनीय वैश्विक रक्षा आपूर्तिकर्ता के रूप में स्थापित करने के लिए एक मजबूत घरेलू रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र आवश्यक है।

एक मजबूत रक्षा औद्योगिक आधार क्यों मायने रखता है

1. रणनीतिक और राष्ट्रीय सुरक्षा अनिवार्यताएँ

- भारत को यूरोप और पश्चिम एशिया में संघर्षों के कारण उजागर आपूर्ति-श्रृंखला की कमजोरियों के साथ-साथ लगातार भूमि और समुद्री सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
- आयात पर अत्यधिक निर्भरता रणनीतिक नाजुकता पैदा करती है, खासकर भू-राजनीतिक संकट के दौरान।
- रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता परिचालन तत्परता और लचीलापन सुनिश्चित करती है।

2. आर्थिक और औद्योगिक महत्व

- रक्षा विनिर्माण पूंजी-गहन और प्रौद्योगिकी-संचालित है, जो उत्पन्न करता है:
 - उच्च कुशल रोजगार
 - एयरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, धातु विज्ञान, एआई और उन्नत विनिर्माण में स्पिलओवर
- रक्षा निर्यात से विदेशी मुद्रा आय में वृद्धि होती है और चालू खाते का बोझ कम होता है।

3. भू-राजनीतिक उत्तोलन

- रक्षा निर्यात तकनीकी परिपक्वता और रणनीतिक विश्वसनीयता का संकेत देता है।
- रक्षा उपकरणों की आपूर्ति राजनयिक साझेदारी को मजबूत करती है, विशेष रूप से विकासशील देशों के साथ जो पारंपरिक आपूर्तिकर्ताओं के लिए लागत प्रभावी विकल्प चाहते हैं।

हाल के सुधार और उपलब्धियाँ

- भारत ने हाल के वर्षों में एक निर्णायक नीतिगत बदलाव देखा है:
- रक्षा विनिर्माण को निजी क्षेत्र के लिए खोलना
- उदारीकृत एफडीआई मानदंड
- आयुध निर्माणी बोर्ड का निगमीकरण
- 'मेक' प्रक्रिया के तहत खरीद का विस्तार
- स्टार्टअप्स और रक्षा नवाचार इकोसिस्टम को बढ़ावा देना

परिणामस्वरूप:

- रक्षा उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है
- निर्यात अब 80 से अधिक देशों तक पहुंच गया है
- भारत तेजी से वैश्विक रक्षा आपूर्ति श्रृंखलाओं में एकीकृत हो रहा है
- ये रुझान एक परिपक्व रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र का संकेत देते हैं।

लगातार चुनौतियाँ

- प्रगति के बावजूद, कई बाधाएँ बनी हुई हैं:

नियामक और प्रक्रियात्मक देरी

- निर्यात लाइसेंसिंग, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण अनुमोदन और संयुक्त उद्यम मंजूरी में समय लगता है।
- एमएसएमई और स्टार्टअप को अनुपातहीन अनुपालन बोझ का सामना करना पड़ता है।

वित्तीय बाधाएं

- प्रतिस्पर्धी ऋण और निर्यात वित्तपोषण तक सीमित पहुंच।

- विशेष रक्षा निर्यात वित्तपोषण साधनों का अभाव।

परीक्षण, प्रमाणन और मानक

- लंबे परीक्षण और अत्यधिक कड़े घरेलू मानक प्रतिस्पर्धा को कम करते हैं।
- अंतरराष्ट्रीय प्रमाणन प्रोटोकॉल के साथ संरेखण का अभाव।

संस्थागत विखंडन

- मंत्रालयों के बीच समन्वय अंतराल निर्यात सुविधा और पहुंच में बाधा डालता है।

डीआरडीओ और संस्थागत सुधारों की भूमिका

- रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की भूमिका विकसित होनी चाहिए:
- डीआरडीओ को सीमांत अनुसंधान और रणनीतिक प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए
- उत्पादन, स्केलिंग और व्यावसायीकरण को सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के उद्योग में तेजी से स्थानांतरित करना चाहिए
- यह प्रभाग वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रतिबिंबित करता है और दक्षता बढ़ाता है
- इसके अतिरिक्त, पेशेवर स्टाफिंग के साथ एक समर्पित रक्षा निर्यात सुविधा एजेंसी का निर्माण कर सकता है:
- एकल-विंडो इंटरफ़ेस प्रदान करें
- समन्वय में सुधार करें
- एक रक्षा भागीदार के रूप में भारत की विश्वसनीयता बढ़ाना

आगे की राह

- 2029 तक रक्षा निर्यात में ₹50,000 करोड़ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, भारत को यह करना होगा:
- नियामक प्रक्रियाओं को सरल और डिजिटाइज़ करें
- उद्योग को दीर्घकालिक मांग दृश्यता प्रदान करें
- निर्यात वित्तपोषण, परीक्षण बुनियादी ढांचे और प्रमाणन प्रणालियों को मजबूत करना
- सरकार-से-सरकार समझौतों, ऋण की लाइनों और दीर्घकालिक सेवा प्रतिबद्धताओं का रणनीतिक रूप से उपयोग करें
- नीति निरंतरता और सुधार की गहराई सुनिश्चित करें

निष्कर्ष

एक मजबूत रक्षा औद्योगिक आधार केवल सैन्य तैयारियों का एक घटक नहीं है; यह आर्थिक ताकत, तकनीकी प्रगति और भू-राजनीतिक प्रभाव का एक स्तंभ है। रक्षा विनिर्माण और निर्यात में भारत की हालिया प्रगति उत्साहजनक है, लेकिन इसकी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए निरंतर सुधार आवश्यक हैं। जैसे-जैसे भारत 2047 की ओर आगे बढ़ रहा है, एक लचीला, अभिनव और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी रक्षा उद्योग एक आत्मविश्वासी, सक्षम और प्रभावशाली वैश्विक शक्ति के रूप में उभरने के लिए अपरिहार्य होगा।